अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 59 | श्री विजय पुरम, रविवार, 01 मार्च 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर से 14 वर्षीय लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया

भारत में गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर के खिलाफ लड़ाई में बड़ी उपलब्धि : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 28 फरवरी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के अजमेर में 14 वर्षीय लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया, जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कर्तव्य भवन से वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी. के. पॉल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास, सफदरजंग अस्पताल के निदेशक डॉ. संदीप बंसल और एम्स नई दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल, आरएमएल अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारी एवं चिकित्सक भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान को भारत की श्नारी शक्तिश को सशक्त बनाने और देश भर में माताओं–बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, "हम सभी जानते हैं कि जब परिवार में मां बीमार पड़ जाती हैं, तो घर बिखर जाता है। मां स्वस्थ रहती हैं, तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भावना के साथ सरकार ने महिलाओं की सहायता के लिए कई योजनाएं चलाई हैं।"

प्रधानमंत्री ने महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा के प्रति सरकार के संवेदनशील और मिशन–उन्मुख दृष्टिकोण पर जोर देते हुए स्वच्छता पहलों के तहत बड़े पैमाने पर शौचालय निर्माण, किफायती सैनिटरी पैड की उपलब्धता और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे परिवर्तनकारी योजनाओं का उल्लेख किया, जिसने लाखों परिवारों के लिए स्वच्छ खाना पकाने के एचपीवी टीकाकरण को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और भारत के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) सहित वैश्विक और राष्ट्रीय विशेषज्ञ निकायों ने मान्य और अनुशंसित किया है।

विश्व स्तर पर, 194 देशों में से 160 देशों ने अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों के तहत एचपीवी टीके को शामिल किया है। इनमें से 90 देशों ने एकल खुराक वाली टीकाकरण प्रणाली अपनाई है, जिनमें दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों का बहुमत शामिल है। 80 देश अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में गार्डसिल–4 टीके का उपयोग कर रहे हैं। इनमें से 61 देश गार्डसिल–4 की एकल खुराक वाली टीकाकरण प्रणाली को लागू कर रहे हैं।

एचपीवी टीके उन एचपीवी प्रकारों के कारण होने वाले गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकने में 93–100 प्रतिशत तक प्रभावी हैं, जिन पर टीकाकरण का दायरा सीमित है। साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि उच्च टीकाकरण कवरेज एचपीवी स्ट्रेन के प्रसार को कम करता है, जिससे बिना टीकाकरण वाले लोगों को भी अप्रत्यक्ष सुरक्षा मिलती है।

भारत का राष्ट्रीय कार्यक्रम वैश्विक वैज्ञानिक साक्ष्यों और डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों के अनुरूप, एकल खुराक अनुसूची में गार्डसिल–4 (क्वाड्रिवेलेंटरू एचपीवी प्रकार 6, 11, 16, 18) का उपयोग करता है।

लक्षित जनसंख्या और कवरेज:

इस अभियान में 14 वर्ष की आयु की लड़कियां (वे लड़कियां जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन अभी 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है) शामिल होंगी। भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) के 2021 के अनुमानों के अनुसार, 14 वर्ष की आयु की लड़कियों का वार्षिक समूह लगभग 1.2 करोड़ है, जिन्हें इस पहल से प्रतिवर्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

एचपीवी टीकाकरण अभियान की परिचालन योजना :

भारत में एचपीवी टीकाकरण की शुरुआत की योजना सुरक्षा, व्यवस्था और निगरानी पर विस्तृत ध्यान देते हुए सावधानीपूर्वक बनाई गई है।

प्रमुख विशेषताएं:

टीकाकरण की अवधिः अभियान मोड में 3 महीने (90 दिन)। अभियान चरण की समाप्ति के बाद, एचपीवी वैक्सीन नियमित टीकाकरण सत्र के दिनों में उपलब्ध होगी।

सत्र स्थलः आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), उप–जिला अस्पताल (एसडीएच), जिला अस्पताल (डीएच), सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) जैसी केवल सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं।

खुराक और दवा देनाः बाएं ऊपरी बांह में एकल खुराक (0.5 मिली) इंट्रामस्कुलर (आईएम) इंजेक्शन।

टीकाकरण स्वैच्छिक है, निःशुल्क है और माता–पिता/अभिभावक की सहमति के बाद ही किया जाएगा।

लाभार्थी यू–विन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूर्व–पंजीकरण और अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, या नामित सरकारी

शेष पृष्ठ 4 पर

गाराचरामा ज़िला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में द्वीपों में भी एचपीवी टीकाकरण अभियान प्रारम्भ

श्री विजय पुरम, 28 फरवरी

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में एचपीवी टीकाकरण अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ किया, जो देशभर में महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी क्रम में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में भी आज ज़िला अस्पताल, गाराचरामा में एचपीवी टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य किशोरियों को गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर से सुरक्षा प्रदान करना है।

द्वीपसमूह में इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. सचिन शिंदे (आईएएस), आयुक्त–सह–सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले सामान्य कैंसरों में से एक है, किंतु इसे टीकाकरण एवं समय पर जांच के माध्यम से रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि एचपीवी वैक्सीन सुरक्षित एवं प्रभावी है। उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं समुदाय के सदस्यों से कार्यक्रम का समर्थन करने तथा सभी पात्र बालिकाओं को टीका दिलाने का आग्रह किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम द्वीपसमूह में सफलतापूर्वक लागू होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती वंदना राव (आईएएस), सचिव

(स्वास्थ्य) एवं प्रबंध निदेशक, केन्द्रशासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन (यूटीएचएम) उपस्थित रहीं। अपने संबोधन में उन्होंने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में एचपीवी टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने जानकारी दी कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी (जिनका 14वां जन्मदिन हो चुका है परंतु 15 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं) सभी बालिकाएं इस टीके के लिए पात्र हैं। उन्होंने अभिभावकों एवं संरक्षकों से अपनी बेटियों को निकटतम

शेष पृष्ठ 4 पर

अतिक्रमण बेदखली अभियान जारी

ब्रुक्शाबाद, स्कूल लाइन तथा अस्टीनाबाद में अवैध संरचनाएं ध्वस्त की गईं

श्री विजय पुरम, 28 फरवरी

सामुदायिक स्थलों के संरक्षण एवं सार्वजनिक संपत्ति के विधिसम्मत उपयोग को सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयासों के तहत ज़िला प्रशासन, दक्षिण अण्डमान द्वारा कड़ी निगरानी रखते हुए सरकारी भूमि को असामाजिक तत्वों के अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में दक्षिण अण्डमान ज़िले में सरकारी भूमि को अतिक्रमण से पुनः प्राप्त करने की कार्रवाई की गई है।

चल रहे अभियान के क्रम में आज ब्रुक्शाबाद, स्कूल लाइन एवं अस्टीनाबाद गांवों में बेदखली कार्रवाई की गई। इस दौरान राजस्व अधिकारियों ने घेराबंदी सहित विभिन्न अतिक्रमणों को हटाया तथा चार अस्थायी ढांचों और निर्माणाधीन दो अस्थायी संरचनाओं सहित कुल छह अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त किया। परिणामस्वरूप लगभग 2000 वर्ग मीटर सरकारी राजस्व भूमि को पुनः सरकारी खाते में बहाल किया गया।

प्रशासन ने अतिक्रमण के प्रति अपनी 'शून्य सहनशीलता' की नीति दोहराते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत कब्ज़ा संबंधित कानूनों के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

दक्षिण अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त विज्ञप्ति में

निवासियों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार के अवैध कब्ज़े से परहेज करें, अन्यथा कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनभागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु ज़िला प्रशासन, दक्षिण अण्डमान ने अतिक्रमण या अवैध निर्माण की सूचना देने के लिए विभिन्न माध्यम उपलब्ध कराए हैं। नागरिक ज़िला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 03192–240127,238881,1070 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप नंबर 9531888844 पर सूचना साझा कर सकते हैं। प्राप्त सभी सूचनाओं को पूर्ण गोपनीयता के साथ संभाला जाएगा, ताकि सूचना देने वाले व्यक्तियों की निजता सुरक्षित रहे। आने वाले दिनों में भी बेदखली अभियान जारी रहेगा, जिससे सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके तथा उसका समुचित उपयोग जनहित में किया जा सके।

पोर्ट ब्लेयर, मायाबंदर, डिगलीपुर तथा कैम्पबेल बे में 14 मार्च को लगेंगी राष्ट्रीय लोक अदालत

श्री विजय पुरम, 28 फरवरी

ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा 14 मार्च, 2026 को ज़िला न्यायालय परिसर, पोर्ट ब्लेयर, उप–मंडलीय न्यायालय परिसर, मायाबंदर, सर्किट कोर्ट, डिगलीपुर तथा कैंपबेल बे में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य मामलों के अतिरिक्त, वाद दायर होने से पूर्व (प्री–लिटिगेशन) स्तर के विवादों का भी राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों की आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा। प्री–लिटिगेशन विवादों में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत मामले, धन वसूली संबंधी मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल से जुड़े मामले (गैर–समझौता योग्य मामलों को छोड़कर), भरण–पोषण संबंधी मामले, दीवानी विवाद तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद शामिल हैं। ऐसे किसी भी प्री–लिटिगेशन या पोस्ट–लिटिगेशन विवाद वाले आम नागरिक 6 मार्च, 2026 से पूर्व अपने विवाद लिखित रूप में सचिव, ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण, पोर्ट ब्लेयर को प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि 14 मार्च, 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु मामलों को तैयार किया जा सके।

'इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)' द्वारा मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

श्री विजय पुरम, 28 फरवरी

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), अण्डमान निकोबार राज्य केंद्र द्वारा अण्डमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माझा संकर्म (एएलएचडब्ल्यू), मोहनपुरा, श्री विजय पुरम के सम्मेलन कक्ष में 'विज्ञान में महिलाएंः विकसित भारत की उत्प्रेरक' विषय पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में दक्षिण अण्डमान की उपायुक्त इंजीनियर पूर्वा गर्ग (आईएएस) मुख्य अतिथि रहीं, जबकि एएलएचडब्ल्यू की उप मुख्य अभियंता इंजीनियर ममता जिजीथ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि ने अपने मुख्य भाषण में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। विशिष्ट अतिथि इंजीनियर ममता जिजीथ तथा चेयरपर्सन एवं काउंसिल सदस्य इंजीनियर उषा स्टीफन, एफआईई ने भी सभा को संबोधित किया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार दो विशिष्ट वक्ताओं–इंजीनियर डायना जोसलिन, विभागाध्यक्ष (सिविल इंजीनियरिंग) एवं डीन (स्टूडेंट अफेयर्स), 'डीब्राइट' तथा इंजीनियर ए. भुवनेश्वरी, सहायक कार्यपालक अभियंता, दीप घर एवं दीप पोत निदेशालय–ने विषय पर संवादात्मक प्रस्तुति एवं व्याख्यान देकर विद्यार्थियों और उपस्थित जनों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में जेएनआरएम एवं 'डीब्राइट' के विद्यार्थी, एएलएचडब्ल्यू, एपीडब्ल्यूडी, डीएलएचएलएस, एसवीपीएमसी तथा अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकारी एजेंसियों के अभियंता तथा आईईआई के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन आईईआई एएनएससी के मानद सचिव इंजीनियर देबदास पैक, एमआईई द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर

पृष्ठ 1 का शेष

स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर टीकाकरण करवा सकते हैं। माता–पिता/अभिभावक की सहमति अनिवार्य है और इसे यू–विन पर डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहां निर्धारित प्रारूप के अनुसार हार्ड कॉपी में सहमति प्राप्त की जा सकती है।

यू–विन प्लेटफॉर्म का उपयोग सत्र की योजना बनाने, पंजीकरण, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए किया जाएगा, जबकि ई–विन पोर्टल वैक्सीन स्टॉक और लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करेगा।

तकनीकी और परिचालन संबंधी सभी पहलुओं को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण अभ्यासों सहित व्यापक तैयारी गतिविधियां चलाई गई हैं। सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विस्तृत दिशानिर्देश साझा किए गए हैं।

इस कार्यक्रम में सख्त चिकित्सा दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है। निम्नलिखित मामलों में टीकाकरण स्थगित या टाला जा सकता है:

- मध्यम या गंभीर बीमारी से पीड़ित लड़कियों के ठीक होने तक
- जिन लड़कियों को पहले के टीकाकरण से गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई हो
- जिन लड़कियों को यीस्ट से एलर्जी होती है
- लक्षित आयु वर्ग से बाहर की लड़कियां

जिन लड़कियों को पहले से ही कोई भी एचपीवी वैक्सीन (गार्डासिल, गार्डासिल–9, सर्वाइरिक्स या सर्वावैक) लग चुकी है, उनकी टीकाकरण स्थिति यू–विन पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी।

सभी टीकाकरण सत्र प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में आयोजित किए जाते हैं, जिनमें कार्यात्मक कोल्ड चेन पॉइंट (सीसीपी) और टीकाकरण के बाद होने वाली किसी भी दुर्लभ प्रतिकूल घटना (एईएफआई) के प्रबंधन के लिए 24×7 सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ाव होता है।

प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू करने के बाद, स्थानीय कार्यक्रमों के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किए गए।

देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान भारत की निवारक स्वास्थ्य देखभाल रणनीति में एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतिनिधित्व करता है और वैज्ञानिक साक्ष्य तथा कार्यान्वयन तत्परता पर आधारित वितरण–उन्मुख शासन को दर्शाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय माता–पिता और अभिभावकों से आग्रह करता है कि वे अभियान अवधि के दौरान अपनी 14 वर्षीय बेटियों को एचपीवी का टीका अवश्य लगवाएं। एचपीवी टीकाकरण एक शक्तिशाली निवारक उपाय है जो जीवन बचा सकता है और भारत की बेटियों के लिए एक स्वस्थ और कैंसर–मुक्त भविष्य सुनिश्चित कर सकता है।

गाराचरामा ज़िला अस्पताल में आयोजित

पृष्ठ 1 का शेष

स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण हेतु ले जाने का अनुरोध किया।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. अविजीत रॉय, उप निदेशक (स्वास्थ्य) एवं राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी के स्वागत एवं मुख्य वक्तव्य से हुई। कार्यक्रम का समापन डॉ. एम. जॉय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ज़िला अस्पताल, गाराचरामा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने सभी गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की किशोरियों के स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता हेतु मायाबंदर में 'वाटर कॉन्सर्ट' आयोजित

मायाबंदर, 28 फरवरी

जल के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने की अपनी सतत पहल के तहत अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा उत्तर व मध्य अण्डमान के ज़िला मुख्यालय मायाबंदर में "वाटर कॉन्सर्ट" शीर्षक से जल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों, जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो सतत जल प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रति समुदाय की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को जल के ज़िम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक करना था। इसमें पेयजल के संयमित उपयोग, जल की बर्बादी रोकने तथा जहां संभव हो, जल के पुनः उपयोग पर विशेष बल दिया गया। रोचक जागरूकता गतिविधियों और संवादात्मक सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को अपने दैनिक जीवन में जल संरक्षण उपाय अपनाने और इस अमूल्य प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहीं, जिनमें मधुर गीतों और नृत्यों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया और दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने जल के उचित एवं ज़िम्मेदार उपयोग का संकल्प लिया। यह अभियान वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों की सुरक्षा हेतु सामूहिक संकल्प का प्रतीक बना।

इस अवसर पर मुख्य अभियंता, एपीडब्ल्यूडी, अपर ज़िला मजिस्ट्रेट, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। उनकी सहभागिता पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रशासन के समन्वित एवं एकीकृत दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।

मायाबंदर के एपीडब्ल्यूडी से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्यक्रम अण्डमान लोक निर्माण विभाग के तत्वावधान में टीम एपीडब्ल्यूडी, मायाबंदर द्वारा आयोजित किया गया। यह पहल द्वीपों में जल संरक्षण प्रयासों के प्रति जनजागरूकता को सुदृढ़ करने एवं सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील दोहराई है कि वे जल संरक्षण उपायों को अपनाएं और संघ राज्य क्षेत्र में सतत जल संसाधन सुनिश्चित करने के सामूहिक मिशन में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

समामेलित लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का सफल समापन

श्री विजय पुरम, 28 फरवरी

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ द्वारा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट (आईएसटीएम) के सहयोग से "पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, एनपीएस एवं आरटीआई" विषय पर पांच दिवसीय परिपेटेटिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, श्री विजय पुरम के सेमिनार गैलरी में किया गया। यह प्रशिक्षण 23 से 27 फरवरी, 2026 तक आयोजित किया गया, जो अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के समामेलित लिपिकीय संवर्ग कर्मचारियों के लिए निर्धारित था। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सरला चक्रवर्ती, सहायक सचिव (प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण/पीजीसी) ने अध्यक्षता की तथा सतत क्षमता निर्माण एवं कुशल प्रशासन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान आईएसटीएम से प्रतिनियुक्त विशेष प्रशिक्षक श्री भगबान पाध्य, उप निदेशक एवं श्री तरुण, सहायक निदेशक ने प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यक्रम का समापन सुश्री जिन्सी जॉय, एलजीसी, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विज्ञान केंद्र में हुए विविध कार्यक्रम

श्री विजय पुरम, 28 फरवरी

विज्ञान केंद्र, श्री विजय पुरम ने आज सर सी.वी. रमन द्वारा खोजे गए 'रमन प्रभाव' की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को अपने परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस वर्ष समारोह की थीम 'विज्ञान में महिलाएं: विकसित भारत की उत्प्रेरक' रही। इस अवसर पर विद्यालयी छात्रों में विज्ञान के प्रति ज्ञान एवं जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। श्री विजय पुरम के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 550 विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. दिलीप कुमार झा, प्रभारी अधिकारी, अटल सेंटर ऑफ ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, श्री विजय पुरम उपस्थित रहे तथा विज्ञान सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को ट्रॉफी एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किए।

अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित नवाचारपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। विज्ञान केंद्र के शिक्षा अधिकारी श्री देबाशीष पॉल ने स्वागत भाषण में कहा कि विज्ञान केंद्र विद्यार्थियों के लिए वैज्ञानिक सोच विकसित करने का उपयुक्त स्थान है, क्योंकि यहां अनेक आकर्षक वैज्ञानिक प्रदर्शनी एवं कार्यक्रम उपलब्ध हैं। विज्ञान केंद्र के क्यूरेटर श्री शाजन थॉमस ने भी विज्ञान सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में सहभागिता पर संतोष व्यक्त किया।

आटम पहाड के प्राथमिक विद्यालय में चौथी टेंट लाइब्रेरी का शुभारंभ

श्री विजय पुरम, 28 फरवरी

परंपरागत कक्षाओं से आगे बढ़कर पठन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के अपने नवाचारपूर्ण प्रयासों को सुदृढ़ करते हुए, द्वीप प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत राज्य पुस्तकालय, श्री विजय पुरम ने कल राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आटम पहाड़ में अपनी चौथी टेंट लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में पठन को समाहित कर उसे रोचक एवं सार्थक बनाना है। मुख्य अतिथि के रूप में पीएम श्री गाराचरामा स्कूल की उप–प्रधानाचार्या श्रीमती ज्योति ने टेंट लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस प्रकार की नवाचारपूर्ण पहलें बच्चों में जिज्ञासा एवं स्वाध्ययन की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करने तथा पढ़ने की आदत को जीवन भर का साथी बनाने के लिए प्रेरित किया। राज्य पुस्तकालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम में जीपीएस, आटम पहाड़ की प्रधानाध्यापिका श्रीमती विजया लक्ष्मी, राज्य पुस्तकालय के प्रभारी, विद्यार्थी, शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। टेंट लाइब्रेरी में बच्चों की आयु के अनुरूप चयनित कहानी–पुस्तकों एवं पठन सामग्री का संग्रह उपलब्ध कराया गया है, जो नन्हे पाठकों की कल्पनाशक्ति एवं सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

'हरित भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी' पर दो दिवसीय कार्यशाला हुई

श्री विजय पुरम, 28 फरवरी

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, अण्डमान तथा निकोबार क्षेत्रीय केंद्र तथा द्वीपीय जैव विविधता पर ईआईएसीपी केंद्र द्वारा 27 फरवरी को प्राणी विज्ञान परिसर में 'हरित भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्घाटन संबोधन में डॉ. रामकृष्ण, पूर्व निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि विज्ञान एक सतत प्राकृतिक प्रक्रिया है और वैज्ञानिक प्रगति प्रकृति के निरंतर नवाचार एवं विकास को दर्शाती है, जिसमें मानव केवल एक भाग है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस अवसर पर डॉ. एम. संजप्पा, पूर्व निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, डॉ. राहुल मोहन, वैज्ञानिक–जी, ध्रुवीय विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा तथा डॉ. के. थियागेसन, पूर्व प्राचार्य, एवीसी कॉलेज (स्वायत्त), तमिलनाडु ने भी 'हरित भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी' विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इससे पूर्व डॉ. सी. शिवपेरुमन, प्रभारी अधिकारी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, अण्डमान तथा निकोबार क्षेत्रीय केंद्र ने उपस्थित जनों का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि यह दिवस वर्ष 1928 में सी.वी. रमन द्वारा 'रमन प्रभाव' की खोज की स्मृति में मनाया जाता है तथा वैज्ञानिक जिज्ञासा, अनुसंधान और आविष्कार की भावना का सम्मान करता है।

स्वराज द्वीप में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम

श्री विजय पुरम, 28 फरवरी।

सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन शाखा एमएसएमई–विकास एवं सुविधा कार्यालय, डॉलीगंज औद्योगिक क्षेत्र, श्री विजय पुरम द्वारा आज स्वराज द्वीप के गोविंद नगर स्थित पंचायत भवन में एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की 48 महिलाओं ने भाग लिया। एमएसएमई योजनाओं एवं उद्यमिता पर तकनीकी सत्र शाखा एमएसएमई–डीएफओ के श्री तनुज द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंक सहायता एवं योजनाओं पर सत्र एएनएससीबी के प्रबंधक प्रभारी श्री सत्यानारायण ने लिया, जबकि उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं एवं उपलब्ध सहायता पर शाखा एमएसएमई–डीएफओ के सहायक निदेशक श्री हरजिंदर सिंह ने प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उद्यमिता के अवसरों, एमएसएमई योजनाओं, ऋण संयोजन (क्रेडिट लिंकज) एवं संस्थागत सहयोग पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

12 टीमों की प्रतिभागिता से 8 मार्च से शुरू होगा आईसीपीएल सीजन–4

श्री विजय पुरम, 28 फरवरी

क्रिकेट एसोसिएशन अण्डमान तथा निकोबार (सीएएएन) द्वारा दक्षिण अण्डमान ज़िला क्रिकेट संघ के सहयोग से आयोजित आइलैंड क्रिकेट प्रीमियर लीग (आईसीपीएल) सीजन–4 का शुभारंभ 8 मार्च, 2026 को श्री विजय पुरम के नेताजी स्टेडियम में होगा। भव्य उद्घाटन समारोह शाम 6 बजे प्रारंभ होगा, जिसके बाद शाम 6.30 बजे फ्लडलाइट्स के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा।

इस सीजन में कुल 12 प्रतिस्पर्धी टीमें भाग लेंगी, जिनमें द्वीपसमूह के श्रेष्ठ क्रिकेट प्रतिभाएं शामिल होंगी। प्रतियोगिता को और रोमांचक बनाने के लिए 24 मुख्यभूमि स्तर के राष्ट्रीय खिलाड़ी भी भाग लेंगे, जिससे आईसीपीएल सीजन–4 अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आयोजित सबसे बड़े क्रिकेट आयोजनों में से एक बन गया है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार आईसीपीएल सीजन–4 क्रिकेट प्रेमियों के लिए हाई–वोल्टेज मुकाबले, रोमांचक प्रदर्शन और यादगार खेल क्षणों का वादा करता है। सीएएएन ने सभी क्रिकेट प्रेमियों, परिवारों, युवाओं एवं खेल समर्थकों से नेताजी स्टेडियम में उपस्थित होकर इस महा आयोजन का साक्षी बनने का आह्वान किया है।

डीजीपी कप टी–20 क्रिकेट टूर्नामेंट

श्री विजय पुरम, 28 फरवरी

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा डीजीपी कप टी–20 राज्य स्तरीय लीग–कम–नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट (सीजन–4) का आयोजन आईआरबीएन मुख्यालय, पोर्ट मोट, दक्षिण अण्डमान के क्रिकेट ग्राउंड तथा नेताजी स्टेडियम, श्री विजय पुरम में किया जाएगा। टूर्नामेंट का शुभारंभ मार्च, 2026 के द्वितीय सप्ताह में निर्धारित है।

विभिन्न विभागों एवं निजी युवा क्लबों की टीमें इस प्रतिष्ठित क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं। प्रत्येक टीम के लिए प्रवेश शुल्क 25,000 रूपए निर्धारित किया गया है। "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर अधिकतम 32 टीमों को ही भागीदारी की अनुमति दी जाएगी।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इच्छुक टीमें अधिक जानकारी हेतु आयोजन समिति के सदस्य श्री वी. हेंथो (मोबाइल: 9933263549) एवं श्री मोहम्मद मुस्तफा (मोबाइल: 993329769) से संपर्क कर सकती हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 7 मार्च, 2026 सायं 5 बजे तक है। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात किसी भी टीम का पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

डिगलीपुर में क्रिकेट चैंपियन लीग का शुभारंभ 3 मार्च से

डिगलीपुर, 28 फरवरी

ज़िला क्रिकेट संघ, उत्तर व मध्य अण्डमान ने क्रिकेट एसोसिएशन अण्डमान तथा निकोबार (सीएएएन) के सहयोग से क्रिकेट चैंपियन लीग के आयोजन की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट 3 मार्च, 2026 से विवेकानंद स्टेडियम, डिगलीपुर में प्रारंभ होगा, जो टीमों को अपनी क्रिकेट प्रतिभा प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट मंच प्रदान करेगा। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर व मध्य अण्डमान की टीमों को इस रोमांचक प्रतियोगिता में पंजीकरण एवं भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है। पंजीकरण हेतु संपर्क नंबर: 9434289000, 8617341884, 9474276213 हैं।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

श्री विजय पुरम, दिनांक 3 फरवरी, 2026

सं. 36/2026/फा. सं. 2-23/2020/Rev.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 11.04.1960 की अधिसूचना संख्या 14/3/60 –ए.एन.एल. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस पद से संबंधित पूर्व की सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन उपायुक्त की स्थापना में धारित **सर्वेक्षक** वर्ग 'ग' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :–**
(i) इन नियमों को "संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (राजस्व विभाग के सर्वेक्षक की वर्ग 'ग' पद) की भर्ती नियमावली, 2025" कहा जाएगा।
(ii) यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :–**
उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं :–**
उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।
4. **अयोग्यताएँ :–** कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने –
क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित है, या
ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो :
परंतु उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी विवाह उस व्यक्ति और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।
5. **ढ़ील देने की शक्ति :–** जहाँ उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।
6. **व्यावृत्ति :–** इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित करना अपेक्षित है।

एडमिरल डी. के. जोशी
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.)
उप राज्यपाल (प्रशासक),
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
(ए. येसु राज)
सहायक सचिव (राजस्व)

अनुसूची
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (राजस्व विभाग) के अधीन उपायुक्त की स्थापना में सर्वेक्षक के पद के लिए भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	**सर्वेक्षक**
2.	पदों की संख्या	44 (चवालीस)* (2024) * कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'ग' अराजपत्रित (अलिपिकीय)
4.	वेतन स्तर	वेतन स्तर – 4 (रु. 25500–81100)
5.	चयन पद या गैर–चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	पुरुष के लिए 18–33 वर्ष महिला के लिए 18–38 वर्ष नोट–I : केंद्रीय सरकार द्वारा पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी। नोट–II : भारत के अन्य स्थानों के उम्मीदवारो से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि होगी और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला और चंबा जिले का पंगी उप–मंडल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ	**अनिवार्य** : (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/उद्योग/प्रतिष्ठान से क्राफ्ट्समेन प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के तहत सर्वेक्षक ट्रेड में एक वर्ष या दो वर्ष का राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (एनटीसी) धारक होना चाहिए। या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/उद्योग/प्रतिष्ठान से शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एटीएस) के तहत सर्वेक्षक ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) धारक होना चाहिए।
		(iii) विभाग या किसी प्राधिकृत भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। **वांछनीय** : संबंधित कार्यक्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे ?	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	02 (दो) वर्ष (सीधी भर्ती से चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकरी द्वारा निर्धारित के अनुसार न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।
10.	भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है ?	**स्थायीकरण के लिए विचार हेतु विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन इस प्रकार है :** 1. सचिव (राजस्व) – अध्यक्ष 2. संबंधित उपायुक्त – सदस्य 3. सहायक सचिव (राजस्व), सचिवालय – सदस्य 4. उप सचिव (कार्मिक/सहायक सचिव कार्मिक) – सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	लागू नहीं

अनुसूची का अनुलग्नक
सर्वेक्षक का कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. प्राकृतिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भूभाग का गाँवों में विभाजन करना।
2. खंडम सीमा और छोटे सर्किटस् बनाना।
3. अवस्थिति का स्केच तैयार करना।
4. 'ए' स्केच तैयार करना।
5. गाँव सीमा/खंडम सीमा, छोटे सर्किटों और व्यक्तिगत खेतों के ट्राईजंक्शन के लिए आयोजना और सर्वेक्षण पत्थर लगाना
6. गाँव सीमा/खंडम सीमा, छोटे सर्किटों और व्यक्तिगत खेतों के ट्राईजंक्शन का चेन द्वारा मापन कार्य।
7. थियोडोलाइट द्वारा ट्रवर्स स्टेशन का मापन कार्य।
8. 'बी' स्केच और 'बी' फील्ड बुक तैयार करना।
9. पुत्तल स्केच तैयार करना।
10. फील्ड मेजरमेंट बुक तैयार करना।
11. भूमि रजिस्टर तैयार करना।
12. व्यक्तिगत प्लॉट के क्षेत्रफल का गणना करना।
13. तकनीकी प्रकृति के अन्य सभी संबंधित कार्य।
14. लोकहित में सौंपे गए अन्य कार्य।

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए फर्मों को पैनल में शामिल करने हेतु
रुचि की पुनः अभिव्यक्ति

फा.सं. 5–109/डीए/एडी(एई)एमआई/ईओआई/एमआईएस/2024–25/615
दिनांक 18.02.2026

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के व्यक्तिगत भूमी/खेत में रोपण कार्य, डिजाइनिंग एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (टपकाने वाली एवं बौछारी सिंचाई यंत्र) के प्रतिस्थापन कार्य में योग्यताधारी विनिर्माताओं/कम्पनियों/नामवर संस्थाओं से अभिरूची आमंत्रित करती है। विनिर्माताओं/ कम्पनियों/संस्थाओं को सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली के सम्बधित डिजाइन एवं प्रतिस्थापन कार्य का पर्याप्त योग्यता होना आवश्यक है। इच्छुक विनिर्माताओं/कम्पनियों/संस्थाओं अपने सम्पूर्ण पार्श्व रूप जैसे इसी कार्य से संबंधित पूर्ववत् योग्यता एवं तकनीकी श्रम शक्ति आदि का विवरण प्रस्तुत कर सकते है।

तकनीकि बोली के मूल्यांकन के पशचात् विभाग द्वारा छांटे गए संबधितों की सूची तैयार की जाएगी इसके लिए रेजिस्ट्रेशन फी रुपए 10,000/– चार्ज किया जाएगा जिसे वापस नही दिया जाएगा। तैयार की गई सूची रेजिस्ट्रेशन की दिनाकं से 3 साल तक के लिए वैध मानी जाएगी।

ई–ओ–आई दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 11/03/2026 के पूर्वाहन 10.00 बजे

ई–ओ–आई दस्तावेज खुलने की तिथि और समय : 12/03/2026 के अपराहन 3.00 बजे

ई ओ आई दस्तावेज वेबसाइट www.eprocure.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

कृषि निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पास बिना कारण बताए किसी या सभी अभिरूची आमंत्रण/तकनीकि बोली को रदद् करने का अधिकार सुरक्षित है।
(Tender ID: 2026_AGPRO_22083_1)

कृषि निदेशक

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, रवीन्द्र नगर, लिटिल अण्डमान की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर(सीसीए)/2025–26/207

कार्य का नाम : लिटिल अण्डमान, रवीन्द्र नगर, ग्राम पंचायत के अंर्तगत रवीन्द्र नगर वार्ड न. 05 में सुधांशु मंडल से नीलकमल रॉय तक ब्लैक टॉप रोड।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 09/03/2026 के सायं 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_22145_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

भारतीय वायु सेना ने राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति 2026 अभ्यास में युद्ध तैयारियों का प्रदर्शन किया

नई दिल्ली, 28 फरवरी।

भारतीय वायुसेना ने आज राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायु शक्ति 2026 अभ्यास किया। इस दौरान वास्तविक युद्ध परिदृश्य में वायुसेना की युद्ध तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने निर्धारित लक्ष्यों पर सटीक हमले किए। सुखोई–30 एमकेआई और मिग–29 विमानों ने कृत्रिम हमले किए। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली ने हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाया।

कुवैत में सुरक्षा हालात के बीच भारतीयों के लिए अलर्ट जारी

नई दिल्ली, 28 फरवरी।

कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए कुवैत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह जारी की है। दूतावास ने परामर्श में भारतीय नागरिकों से सुरक्षा दिशानिर्देशों और सलाहों का पालन करने का आग्रह किया है। परामर्श में कहा गया कि भारतीय नागरिकों को समाचारों और कुवैती सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर नज़र रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कार्यालय ने बताया कि आपात स्थिति में भारतीय नागरिक दूतावास के हेल्पलाइन नंबर + 9 6 5 6 5 5 0 1 9 4 6 पर संपर्क कर सकते हैं या community.kuwait@mea.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं। परामर्श के अनुसार, दूतावास सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

आखिर रविवार को ही क्यों मिलता है वीकऑफ? इसके पीछे छिपी है एक दिलचस्प कहानी

नई दिल्ली, 28 फरवरी।

रविवार का नाम सुनते ही चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। यह दिन परिवार के साथ समय बिताने और काम से ब्रेक का होता है। भारत में रविवार साप्ताहिक छुट्टी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं हमेशा से ऐसा नहीं था।

रविवार को साप्ताहिक छुट्टी चुनने के पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है, जो मजदूरों के अधिकार और ब्रिटिश शासन से जुड़ी है। आइए जानें क्यों रविवार को ही साप्ताहिक छुट्टी के दिन के रूप में चुना गया।

बिना ब्रेक के करना पड़ता था काम

आज हम जिस वीकेंड का आनंद लेते हैं, वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। ब्रिटिश शासन के दौरान, भारत में खासकर मुंबई की कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्हें सप्ताह के सातों दिन बिना किसी ब्रेक के काम करना पड़ता था। लंबे समय तक लगातार काम करने के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इसी मुश्किल समय में उनके नायक बने नारायण मेघाजी लोखंडे।

सात साल का लंबा संघर्ष

मजदूरों के दुख को देखते हुए लोखंडे ने उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। साल 1881 से 1884 के बीच उन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और ब्रिटिश प्रशासन को कई संदेश भेजे। उनकी अपील पर हजारों की संख्या में मजदूर एक साथ आए, लेकिन यह कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। यह आंदोलन पूरे सात साल तक चला। अंत में मजदूरों की एकजुटता और लोखंडे की कोशिशों के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 10 जून 1890 को भारत में रविवार को आधिकारिक रूप से साप्ताहिक छुट्टी घोषित कर दिया गया।

रविवार का दिन ही क्यों चुना गया?

रविवार को ही छुट्टी के लिए चुने जाने के पीछे धार्मिक और व्यावहारिक, दोनों कारण थे–

उस समय भारत में ब्रिटिश हुकुमत थी, जो ईसाई धर्म को मानते थे। उनके लिए रविवार चर्च जाने का दिन था। इसलिए रविवार को छुट्टी के दिन के लिए चुना गया।

एक तर्क भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से जोड़कर भी दिया गया कि रविवार का दिन सूर्य देव और कुछ क्षेत्रों में भगवान खंडोबा को समर्पित है। अंग्रेजों की तरह ही भारतीय मजदूरों को भी आराम और पूजा के लिए एक दिन मिलना चाहिए।

1700 साल पुराना इतिहास

दिलचस्प बात यह है कि रविवार को आराम का दिन बनाने की शुरुआत भारत से नहीं हुई थी। इसका इतिहास बहुत पुराना है। साल 321 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने सबसे पहले पूरे रोमन साम्राज्य में रविवार को आराम का दिन घोषित किया था। धीरे–धीरे यह परंपरा यूरोप और फिर ब्रिटेन के प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बन गई, जिसे वे भारत लेकर आए।

क्यों कुछ लोग अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं? वैज्ञानिकों ने बताया इसके पीछे का असली विलेन

नई दिल्ली, 28 फरवरी।

क्या आप जानते हैं कि बुढ़ापे को लेकर आपकी चिंता ही आपको समय से पहले बूढ़ा बना रही है? जी हां, अगर आप भी उम्र बढ़ने को लेकर हमेशा खौफ में रहते हैं, तो यह आपकी सेहत को काफी भारी नुकसान पहुंचा रहा है।

न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के एक हालिया शोध में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस अध्ययन के अनुसार, उम्र बढ़ने की चिंता, और खास तौर पर भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का डर, हमारे शरीर में बुढ़ापे की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है। यह कोई बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि यह बदलाव हमारे शरीर के भीतर श्कोशिकीय स्तरश पर होता है, जिससे इंसान असल में तेजी से बूढ़ा होने लगता है।

यह महत्वपूर्ण अध्ययन 700 से अधिक महिलाओं पर किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन महिलाओं के मन में अपनी बढ़ती उम्र को लेकर ज्यादा चिंता थी, उनके खून की जांच में जैविक रूप से तेजी से बूढ़े होने के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। विज्ञान की भाषा में इन उम्र बताने वाले लक्षणों को मापने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, उसे एपीजेनेटिक क्लाक्स कहा जाता है।

इस शोध में एक बहुत ही दिलचस्प बात भी सामने आई है। वयस्कों में तेजी से उम्र बढ़ने का यह संबंध मुख्य रूप से बीमारियों के डर, शरीर के कमजोर होने और दूसरों पर निर्भर हो जाने के डर से जुड़ा था। इसके विपरीत, अगर कोई महिला केवल अपनी सुंदरता कम होने या प्रजनन क्षमता को लेकर चिंतित थी, तो उसका प्रभाव शरीर के जल्दी बूढ़े होने की प्रक्रिया पर नहीं दिखा।

इस शोध से जुड़ीं शोधकर्ता मारियाना रोड्रिग्स ने इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि उम्र बढ़ने का डर सिर्फ मन का वहम या कोई मामूली मनोवैज्ञानिक परेशानी नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या है। हालांकि पिछले अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि चिंता और डिप्रेशन का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन यह पहली बार है जब शोधकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि बुढ़ापे को लेकर होने वाली चिंता और शरीर के असल में बूढ़े होने की प्रक्रिया के बीच सीधा और गहरा संबंध है।

आईएमए ने 14 वर्ष तक की किशोरियों के मुफ्त एचपीवी टीकाकरण के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया

नई दिल्ली, 28 फरवरी।

भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने देशभर में 14 वर्ष तक की किशोरियों को मुफ्त एचपीवी टीकाकरण उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में आईएमए ने कहा है कि यह पहल सर्विकल कैंसर की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और देश की लाखों महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

आईएमए ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि देशभर में अपनी 18 सौ से अधिक स्थानीय शाखाओं के माध्यम से वह इस राष्ट्रीय मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है या नहीं, एचपीवी टीकाकरण पर क्या कहते हैं डॉक्टर?

नई दिल्ली, 28 फरवरी।

केंद्र सरकार देशभर में 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण का 90 दिन का विशेष अभियान शुरू करने जा रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुरूप डोर–टू–डोर रणनीति के तहत 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी किशोरियां सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त टीका लगवा सकेंगी। इस वर्ष लगभग 1.15 करोड़ लड़कियां इस आयु वर्ग में शामिल होंगी।

राजधानी दिल्ली में इस राष्ट्रीय अभियान को राज्य की कैंसर रोकथाम रणनीति से जोड़ा जा रहा है। सर गंगा राम अस्पताल की गायनेकोलॉजी एंडोस्कोपी विशेषज्ञ डॉ. कनिका जैन ने एचपीवी वैक्सीनेशन कार्यक्रम को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा कि कम उम्र में, पहले संक्रमण से पहले टीकाकरण 93 से 100 प्रतिशत तक सुरक्षा दे सकता है। उनके अनुसार भारत में हर साल लगभग 80,000 नए मामले सामने आते हैं और करीब 40,000 महिलाओं की मौत इस रोके जा सकने वाले कैंसर से होती है।

दिल्ली में स्थिति और सरकार की रणनीति

राष्ट्रीय राजधानी में वर्ष 2023 में सर्वाइकल कैंसर के 741 मामले दर्ज हुए थे, जो 2025 में घटकर 692 हो गए। हालांकि यह गिरावट सकारात्मक संकेत है, फिर भी यह महिलाओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है।

इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (डीएससीआई) के माध्यम से कैंसर जागरूकता, रोकथाम एवं स्क्रीनिंग कार्यक्रम (कैप्स) शुरू किया है।

दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए प्रमुख कदम

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के अनुसार सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण और समय पर जांच सरकार की प्राथमिकता है। डीएससीआई के निदेशक डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि:

- अत्याधुनिक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वैन मोहल्लों तक पहुंचाई जा रही हैं।
- इन वैनों में मैमोग्राफी और एचपीवी डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध है।
- सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए सेल्फ–टेस्टिंग किट भी दी जा रही है।

सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण क्यों जरूरी है?

वैक्सीन एलायंस 'गावी' के अनुसार भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर प्रमुख कैंसरों में से एक है। हर साल 1.25 लाख महिलाएं इससे ग्रस्त होती हैं और लगभग 75 हजार की मृत्यु हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर टीकाकरण से 30 वर्ष की उम्र तक कैंसर का जोखिम 85 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

स्लॉट कैसे बुक कर सकते हैं?

टीकाकरण के लिए U-WIN पोर्टल के माध्यम से जनसुविधा केंद्र पर पंजीकरण कराया जा सकेगा।

बाजार में कीमत क्या है और सरकार की क्या योजना है?

बाजार में एक डोज की कीमत 3,927 रुपये है। भारत में 'गावी' वैक्सीन एलायंस के सहयोग से कुल 2.6 करोड़ डोज उपलब्ध कराई जाएंगी। यह कार्यक्रम तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

किस वैक्सीन का इस्तेमाल होगा?

शुरुआती दो वर्षों में एचपीवी संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वदेशी वैक्सीन 'सर्वावैक' का उपयोग किया जाएगा। इसे सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है।

यह किन बीमारियों से सुरक्षा देगा?

यह वैक्सीन एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) के टाइप 16 और 18 से सुरक्षा प्रदान करती है, जो सर्वाइकल कैंसर के प्रमुख कारण हैं। साथ ही यह टाइप 6 और 11 से भी बचाव देती है।

कुल मिलाकर, केंद्र का राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान और दिल्ली की सक्रिय स्क्रीनिंग रणनीति मिलकर राजधानी में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम को नई दिशा दे सकती है–जहां लक्ष्य है समय पर पहचान, रोकथाम और सुलभ उपचार।

इतिहास के पन्नों में 01 मार्च: अमेरिका के परमाणु बम परीक्षण से हिल गई धरती

नई दिल्ली, 28 फरवरी।

देश–दुनिया के इतिहास में 01 मार्च की तारीख का अहम स्थान है। दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए तो लगा था कि इनसान इन खतरनाक हथियारों से दूरी बना लेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगले दशक में बिकनी अटोल नाम की जगह पर दर्जनों परमाणु बम परीक्षण किए। इनमें से ही एक था श्कैसल ब्रावोश परीक्षण। यह अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी परमाणु परीक्षण है। इसे 1954 में 01 मार्च को किया गया था।

बिकिनी अटोल प्रशांत महासागर में एक कोरल आइलैंड है। इसका आकार अंगूठी जैसा है। इसमें 23 छोटे कोरल द्वीप हैं। यह हवाई और फिलीपींस के बीच स्थित है। परमाणु परीक्षण के बाद अटोल दुनिया की सबसे मशहूर जगहों से एक बन गया। एक फ्रांसीसी डिजाइनर ने तो इसके नाम पर एक स्विमिंग सूट का नाम तक रख दिया। ब्रावो से 150 लाख टन का धमाका हुआ। यह धमाका हिरोशिमा पर गिराए गए बम से हजार गुना ज्यादा बड़ा था। धमाके से करीब दो किलोमीटर चौड़ा छेद बन गया। बिकनी से लगभग 160 किलोमीटर दूर के द्वीप पर जोरदार विस्फोट से जमीन हिलने लगी थी। कुछ घंटों बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ लोगों पर, पीने के पानी में और भोजन पर गिरने लगा। विस्फोट के करीब के द्वीप के निवासियों को वहां से हटाया गया। 1964 में अमेरिका की सरकार ने माना कि उनकी गलती से द्वीप के लोग रेडिएशन के संपर्क में आए। इसकी भरपाई के लिए सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा दिया। यूनेस्को ने 2010 में बिकिनी अटोल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। उसने कहा कि यह साइट शीत युद्ध के जन्म और न्यूकलियर हथियार विकसित करने की होड़ का ठोस प्रमाण है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1640: ब्रिटेन को मद्रास में बिजनेस सेंटर बनाने की इजाजत मिली।

1775: अंग्रेजी हुकूमत और नाना फडनवीस के बीच पुरंधर की संधि पर हस्ताक्षर।

1872: अमेरिका में दुनिया का पहला राष्ट्रीय पार्क स्थापित किया गया। पश्चिमी अमेरिका में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क को 1978 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया।

1919: महात्मा गांधी ने रॉलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने की इच्छा जाहिर की।

1962: पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने नया संविधान अंगीकार करने का ऐलान किया, जिसमें देश में राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली शासन प्रणाली की हिमायत की गई।

1969: पहली सुपर फास्ट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली और कलकत्ता (अब कोलकाता) के बीच चलाई गई।

1973: फिलीस्तीन के सशस्त्र समूह ब्लैक सैपटैंबर ने खारतूम में सऊदी अरब के दूतावास पर कब्जा कर लिया और वहां मौजूद राजनयिकों को बंधक बना लिया।

2003: पाकिस्तान में अधिकारियों ने खालिद शेख मोहम्मद को गिरतार किया, जिसे अलकायदा का शीर्ष सदस्य माना जाता था और जिसने अमेरिका पर 2001 में 11 सितंबर को हुए आतंकी हमले की योजना बनाई थी।

2006: तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश भारत की राजकीय यात्रा पर पहुंचे।

2007: अमूल्य नाथ शर्मा नेपाल के पहले बिशप बने।

2010: हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4–1 से मात दी।

जन्म

1917–प्रसिद्ध साहित्यकार करतार सिंह दुग्गल।

1951– बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

1968 – भारतीय महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी कुंजारानी देवी।

1983 – भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम।

1992 – भारतीय पैरा एथलीट शरद कुमार।

1994: कनाडा के गायक जस्टिन बीबर। बीबर ने छोटी उम्र में ही अपने गायन से दुनियाभर में अपने करोड़ों प्रशंसक बना लिए।

खबरों और रोचक जानकारियों के लिए पढ़िए
'द्वीप समाचार'

जीएसटी कटौती से मांग मजबूत, तीसरी तिमाही में जीडीपी 8.3 प्रतिशत रहने का अनुमानः रिपोर्ट

नई दिल्ली, 28 फरवरी।

मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत तक रह सकती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती से मांग में आई मजबूती इस वृद्धि का प्रमुख कारण है, हालांकि पिछले वर्ष के ऊंचे आधार का असर भी बना रहेगा।

जीवीए वृद्धि दर में सुधार का अनुमान

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वृद्धि दर 8 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के 6.5 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि यह दूसरी तिमाही के 8.1 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी कम रह सकती है।

नॉमिनल जीडीपी वृद्धि में नरमी

रिपोर्ट के मुताबिक, नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर घटकर 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो दूसरी तिमाही के 8.7 प्रतिशत और पिछले वर्ष की समान अवधि के 10.3 प्रतिशत से कम है। इसका मुख्य कारण महंगाई में कमी से जीडीपी डिलेटर में आई गिरावट बताया गया है।

नए बेस ईयर को लेकर अनिश्चितता

बैंक ने कहा कि उसके अनुमान पुराने बेस ईयर पर आधारित हैं, क्योंकि बेस ईयर में बदलाव के बाद जीडीपी आंकड़ों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है।

आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय शुक्रवार को 2022–23 के संशोधित बेस ईयर के साथ जीडीपी आंकड़े जारी करेगा। सरकार पहले ही वित्त वर्ष 2022–23 को नई श्रृंखला के लिए बेस ईयर चुन चुकी है, जिससे खासकर निजी कंपनियों और एमएसएमई क्षेत्रों से जुड़े अनुमानों को अधिक सटीक बनाने का प्रयास किया गया है।

वृद्धि के दीर्घकालिक संकेत सकारात्मक

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए वृद्धि का अनुमान फिलहाल मजबूत बना हुआ है और वित्त वर्ष 2027 के शुरुआती संकेत भी सकारात्मक हैं। हालांकि नए बेस ईयर पर स्पष्टता आने के बाद वार्षिक अनुमानों की दोबारा समीक्षा की जाएगी।

टैरिफ अनिश्चितता के बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने दिया भारत के हितों की रक्षा का भरोसा

नई दिल्ली, 28 फरवरी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा पहले घोषित टैरिफ बढ़ोतरी को रद्द किए जाने के बाद बदली हुई स्थिति को देखते हुए, यदि आवश्यक हुआ तो भारत अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते में फिर से संतुलन लाने का प्रयास करेगा।

बदलते हालात पर भारत की नजर

गोयल ने एक मीडिया इवेंट में कहा, "अमेरिकी टैरिफ को लेकर बदलती स्थिति को देखते हुए हम हालात पर नजर रखेंगे और भारत के हितों की रक्षा सुनिश्चित करेंगे।" उन्होंने कहा कि हालात लगातार बदल रहे हैं और प्रशासन के पास विभिन्न उपाय मौजूद हैं, जिनका वे इस्तेमाल कर सकते हैं।

टैरिफ पर संभावित फैसलों का असर

उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से आगे भी कई कदम उठाए जा सकते हैं, जिनमें टैरिफ को 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की संभावना भी शामिल है। गोयल ने कहा कि यदि हालात बदलते हैं तो समझौते में फिर से संतुलन स्थापित किया जाएगा।

द्विपक्षीय वार्ता जारी, सकारात्मक संकेत

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत–अमेरिका के संयुक्त बयान में भी यह स्पष्ट किया गया है कि परिस्थितियों में बदलाव होने पर समझौते को संतुलित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बदलती परिस्थितियों के बीच अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता जारी है और समझौते के कई सकारात्मक पहलू सामने आए हैं।

संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा पर जोर

गोयल ने दोहराया कि प्रस्तावित व्यवस्था में भारत के संवेदनशील डेयरी और कृषि क्षेत्रों को संरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष भारत के निर्यात में वृद्धि की संभावना है।

बैठक पुनर्निर्धारित, नई तारीख जल्द

भारत और वाशिंगटन ने अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर आधिकारिक बैठक को पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया है, ताकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभावों पर विस्तार से विचार किया जा सके। दोनों देशों के मुख्य व्यापार वार्ताकारों के नेतृत्व वाली टीमों के बीच तीन दिवसीय बैठक पहले 23 फरवरी को अमेरिका में प्रस्तावित थी, जिसकी नई तारीख जल्द तय की जाएगी।

एआई के उपयोग में विश्वसनीयता बेहद महत्वपूर्ण है: केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली, 28 फरवरी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एआई के उपयोग में विश्वसनीयता बेहद महत्वपूर्ण है। आज दोपहर नई दिल्ली में एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित राइजिंग भारत समिट को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने एआई परिवर्तन को गंभीरता से लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर कदम सक्रिय रूप से उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिभाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे रही है और इस दिशा में राज्य सरकारों को भी काफी प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने लगभग चार साल पहले आईटी उद्योग के साथ साझेदारी में यूचर स्किल प्रोग्राम शुरू किया था।

वेकेशन पर जाने की कर रहे हैं तैयारी? प्लानिंग में न करें 5 भूल, वरना बीच सफर बिगड़ जाएगा बजट

नई दिल्ली, 28 फरवरी।

बजट के अंदर ट्रैवलिंग करने का मतलब यह कतई नहीं कि आप किसी सस्ते से होस्टल में रात गुजारें और जैसे–तैसे खाकर अपनी छुट्टियां बिता लें। अगर बजट के अंदर ट्रैवल करने की तैयारी इसकी प्लानिंग के समय ही कर ली जाए तो फिर आगे का सफर आसान हो जाएगा।

यहां बात हो रही बजट फ्रेंडली ट्रैवल प्लानिंग की, जिसकी शुरुआत यात्रा शुरू करने के काफी पहले से हो जाती है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं।

अगर नहीं जा पा रहे हैं ड्रीम डेस्टिनेशन

ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि आप अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक नहीं जा पा रहे तो आपको ट्रिप ही कैंसिल कर देने की जरूरत है। आप उस जैसी दूसरी जगहों के ऑप्शन भी देख सकते हैं, जहां जाना ज्यादा सस्ता और बेहतर हो। जैसे कुछ हिल स्टेशंस ज्यादा महंगे होते हैं तो आप उससे मिलती–जुलती जगह जाने का प्लान कर सकते हैं।

कोई एक खास डेट ना चुनें

अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक ही समय पर काफी सारे लोग एक जगह पर ही जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इससे वहां जाना और रहना महंगा पड़ सकता है। ज्यादा भीड़ की वजह से आपका मजा भी किरकिरा हो सकता है। इसलिए, आप अपने ट्रैवल टाइम में थोड़ा बदलाव लाकर समझदारी से प्लानिंग कर सकते हैं।

हर समय ऐसा नहीं होता

लोगों को लगता है कि होटल के मुकाबले एयरबीएनबी या वीआरबीओ जैसे ऑप्शन ज्यादा सस्ते होते हैं। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। कुछ होटल ब्रांड्स कम कीमत पर भी रहने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो होस्टल भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, बस उसकी रेटिंग पहले ही चेक कर लें।

शहर के बीचोंबीच रहने से बचें

किसी भी शहर का मुख्य इलाका ज्यादा महंगा होता है, ऐसे में इन जगहों पर ठहरना या खाना आपके बजट पर असर डाल सकता है। इसलिए, शहर से थोड़ा दूर भी रहने का ठिकाना देख सकते हैं। इन जगहों पर आपको रहने के साथ–साथ, खाना और बाकी एक्टिविटीज भी सस्ती मिल सकती है।

कैश में करें तो ज्यादा बेहतर है

अगर आप ट्रैवल से जुड़े खर्चे क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको बजट का अंदाजा नहीं रहेगा और जरूरत से ज्यादा खर्च होने का खतरा हो सकता है। इससे बचने के लिए कैश या फिर पॉइंट्स में पेमेंट करें।